(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शेष जुताऊ भूमि में से कितने प्रतिशत भूमि को कृषि हेतु उपयोग में लाया जाएगा ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1990–91 के भू-उपयोग के आंकड़ों (अध्यतन उपलब्ध) के अनुसार, देश में खेती योग्य कुल रकबा 184.35 मिलियन हैक्टेयर आंका गया था ।

(ख) भू-उपयोग के उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कृष्य रकबा (निवल बुआई क्षेत्र+चालू परती भूमि) 156.04 मिलियन हैक्टेयर आंका गया है ।

(ग) और (घ) सरकार अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के रकबे में लाने के लिए भूमि सुधार तथा बंजर भूमि विकास संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम नामतः क्षारीय मृदा सुधार के अंतर्गत 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 150 करोड़ रुपए है । इसके अलावा, बंजर भूमि विकास विभाग भी कुछ बंजर भूमि का उपचार कर रहा होगा ताकि उसे वायोमास उत्पादन, विशेषकर ईंधन, लकड़ी तथा चारा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सतत उपयोग में लाया जा सके, जिसके लिए अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

स्माल फारमर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम

6046. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में छोटे किसानों के हितों के संरक्षण हेतु "स्माल फारमर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम" की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी ;

(ग) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई हैं ताकि छोटे किसान इससे सहज रूप से लाभान्वित हो सकें ; और

(घ) यदि हां, तो किस-किस राज्य में कितनी-कितनी शाखाएं अब तक स्थापित की गई हैं और देश में कुल कितनी शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) जी, हां

(ख) दिनांक 18 जनवरी, 1994 को ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन द्वारा लाल मिर्च का निर्यात किया जाना

6047. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोओपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन पिछले कुछ वर्षों से लाल मिर्च का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान किस-किस देश को कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य की लाल मिर्च निर्यात की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन वर्षों के दौरान घटिया किस्म की लाल मिर्च का भी निर्यात किया गया था जिसके कारण फैडरेशन को आर्थिक हानि हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो किस-किस देश को प्रत्येक वर्ष घटिया किस्म की लाल मिर्च का

निर्यात किया गया जिसके परिणामस्वरूप फैडरेशन को कितनी आर्थिक हानि उठा पड़ी ; और

(ङ) क्या इसके लिए दोषी व्यक्तियों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो उनके नाम और पदनाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान निर्यात की गई लाल मिर्च की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (लाख रुपए)	देश
1992–93	शून्य	—	—
1993–94	207	34.55	श्रीलंका
	115	17.25	बंगलादेश

(ग) से (ङ) वर्ष 1993–94 के दौरान, लाल मिर्च की घटिया क्वालिटी की कोई मात्रा निर्यात नहीं की गई, जिससे नेफेड को आर्थिक नुकसान हुआ हो । तथापि, 1991–92 के दौरान 2888 मीटरी टन के कुल निर्यात में से 137 मीटरी टन की एक खेप लदान-पूर्व परीक्षण किए बगैर ही भेज दी गई, जिसकी वजह से 2.2 लाख रुपए मूल्य का 5 प्रतिशत का क्वालिटी दावा स्वीकार करना पड़ा । इस लापरवाही के लिए नेफेड के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है । बहरहाल, 1991–92 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात से लगभग 60.00 लाख रुपए का कुल मुनाफा हुआ ।

दिल्ली दुग्ध योजना में हो रहा घाटा

6048. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत चलने वाली दिल्ली दुग्ध योजना को रोज लाखों रुपए का घाटा हो रहा है जबकि दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत चलने वाली मदर डेयरी कम दर पर दूध की बिक्री करते हुए भी मुनाफे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1992–93 के दौरान दूध की खरीद और वितरण में भारी धांधली हुई थी ; जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सरकार को 1993 में भारी घाटा उठाना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितना घाटा हुआ और क्या सरकार ने दूध की खरीद और वितरण में की गई धांधली और ठेकेदारों को अधिक दर पर कीमत मंजूर न करने वाले अधिकारियों को हटा दिए जाने तथा दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिदिन होने वाले घाटे आदि की कोई जांच कराई है / कोई निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) यह सही है कि दिल्ली दुग्ध योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक मदर डेयरी की तुलना में हानि उठा रही है । किन्तु यह सही नहीं है कि मदर डेयरी अपना दूध कम मूल्य पर बेच रही है । वास्तव में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पौली पैक में बेचे जाने वाले टोन्ड दूध और मदर डेयरी द्वारा अपनी वैण्डिंग मशीनों के माध्यम से बेचे